भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 123
फाइल सं. पीसी-VII/2018/आरएसआरपी/1

आरबीई सं. 197/2018
नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 - संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के विकल्प में संशोधन का अवसर दिया जाना।

कृपया आरएस(आरपी) नियमावली, 2016 द्वारा यथा अधिसूचित 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुने जाने के संबंध में आरएस(आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 5 एवं 6 का अवलोकन करें । उक्त विकल्प उक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात 28.07.2016 से तीन माह के भीतर चुना जाना था । इन नियमों के नियम 6(4) में प्रावधान है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा ।

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने **दिनांक 12.12.2018 के का.ज्ञा. सं. 4-13/17-आईसी/ई-IIIए** के तहत सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस(आरपी) नियमवाली, 2016 के नियम 5 एवं 6 के संबंध में अपने पहले विकल्प को संशोधित करने का अवसर प्रदान किया है । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए ये आदेश आरएस(आरपी) नियमावली, 2016 के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित रेलों पर भी लागू होंगे।

3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12.12.2018 के उक्त का.ज्ञा. के पैरा 3 में उल्लिखित तीन माह की अवधि, इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से तीन माह तक की होगी।

4. यह मामला मान्यताप्राप्त दोनों स्टाफ फेडरेशनों एआईआरएफ और एनएफआईआर द्वारा भी उठाया गया है ।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

सं. 4-13/17-आईसी/ई-III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली / 2 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016- संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के विकल्प में संशोधन का अवसर दिया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के लिए विकल्प चुने जाने के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 5 और 6 की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विकल्प उपर्युक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25.07.2016 से तीन माह के अंदर चुना जाना था। इन नियमों के नियम 6(4) में प्रावधान है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।

2. राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शी तंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया है कि कुछ कर्मचारियों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए। इस मंत्रालय को भी यह प्रस्ताव करते हुए अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि प्रभावित कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए।

3. इस मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने विनिश्चय किया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 6(4) में उल्लिखित शर्त में छूट देते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पहले ही चयन कर चुके हैं, उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार अपने पहले विकल्प को संशोधित करने का एक और अवसर दिया जाएगा। संशोधित विकल्प का प्रयोग इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 3 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। इन आदेशों के अनुसार एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त नियम 5 और 6 में यथानिर्धारित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें लागू रहेंगी।

अमलाथ

4. यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने 01.01.2016 से ही संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना है या जिनके मामले में संशोधित वेतन संरचना 01.01.2016 से लागू है, और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 5 के अनुसार 01.01.2016 के बाद की तारीख से इन आदेशों के तहत संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पुन: प्रयोग करेंगे, उनसे 01.01.2016 से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प के चयन की तारीख तक आहरित संशोधित वेतन के फलस्वरूप उन्हें दी गई बकाया राशि वसूल ली जाएगी।

5. भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. गार्ड फाइल
3. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No. 123 **RBE No.197/2018**
File No. PC-VII/2018/RSRP/1 **New Delhi, dated 17 .12.2018**

The General Managers/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 – opportunity for revision of option to come over to revised pay structure.

Please refer to Rule 5 & 6 of RS(RP) Rules, 2016 regarding exercise of option to come over to revised pay structure effective from 01.01.2016 as notified by the RS(RP) Rules, 2016. The said option was to be exercised within 3 months of the date of notification i.e. 28.07.2016 of the said Rules. The Rule 6(4) thereof provides that the option once exercised shall be final.

2. In this context, it is stated that Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their **OM No. 4-13/17-IC/E-IIIA dated 12.12.2018** permitted opportunity to Government Servants to revise their initial option in terms of Rule 5 & 6 of CCS(RP) Rules, 2016. These orders issued by Ministry of Finance, Department of Expenditure shall be applicable ***mutatis mutandis*** in Railways with respect to RS(RP) Rules, 2016.

3. The 'three months' period mentioned in para 3 of aforesaid OM of Ministry of Finance, Department of Expenditure dated 12.12.2018 shall be three months from the date of issue of these instructions.

4. The matter has also been raised by both recognised Staff Federations AIRF and NFIR.

5. Hindi version will follow.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2018/RSRP/1 **New Delhi, dated 17 .12.2018**

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

File No. PC-VII/2018/RSRP/1 **New Delhi, dated 17 .12.2018**

Copy forwarded to:-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const).

2. The DG, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway
6. The CAO and FA&CAO, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai
8. The CAO(MTP(R) Chennai
9. The Director, CAMTECH/Gwalior
10. The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune (c) IRIMEE, Jamalpur (d) IRISET, Secunderabad
11. The Managing Directors RITES, IRCON, CRIS, IRFC, CONCOR, RVNL, DFCCIL, KRCL.
12. The Chairman-cum-Managing Director, Konkan Railway Corporation, New Delhi.
13. The Pay & Accounts Officer, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
15. The Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
16. Executive Director (Finance), RDSO, Lucknow.
17. The Chairman, RCC Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
18. The Chairman, RRT, Chennai.
19. The Chairman, RCT.
20. The Chairman RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
21. The Editor, 'Bhartiya Rail'.
22. The Editor, 'Indian Railways'.
23. The Chairman, Passenger Services Committee.
24. The Chairman, Passenger Amenities Committee.
25. The C.A.O. (A) MTP (G)/ Mumbai (B) MTP (G)/Chennai.
26. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
27. The Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad.
28. The C.A.O. (Const.), Central Railway, Mumbai.
29. The Liaison Officer, VII CPC, All Indian Railways and PUs/RDSO/Trg. Institutes Metro Railway/COFMOW/CORE/RSC etc.
30. The Director (Movement) Railways/Calcutta.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2018/RSRP/1 **New Delhi, dated 17.12.2018**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan (with 35 spares)
2. The General Secretary, NFIR, Room No. 256 E, Rail Bhawan (with 35 spares)
3. Copy to all members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi (with 40 spares)
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers' Association.
5. All India SC/ST Railway Employee's Association, Room No. 7, Rail Bhawan.
6. All India O.B.C. Railway Employee's Federation, Room No. 48, Rail Bhawan
7. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhawan.
8. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation
9. The Secretary, Railway Board Secretariat Service, Group 'A' Officers Association. Room No. 402, Rail Bhawan.
10. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association.

11. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
12. The Secretary, Non-Ministerial Staff Association (Railway Board).

For Secretary, Railway Board

Copy to:-

PSOs/Sr.PPSs/PPSs/PSs/PAs to:-
MR, MSR(S), MSR(G), CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, DG(Pers.), All Additional Members/Advisors/Executive Directors/Joint Secretaries.

Cash - I, II, & III, Budget, E(P&A) I & II, E(G), E(NG) I & II, PC – III, PC-IV, PC-V, PC-VI, E(LR) I & II, F(E) - I, II & III, F(E) Special, Security (E), Accounts III, ERB - I, II, III, IV, V & VI, G(Pass), G(Acc), RB(Welfare), E(SCT) I & II, E(O) I, II III & III(CC), E(GR) I & II, E(GP), E(GC), PR, branches of Railway Board.

No. 4-13/17-IC/E-IIIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 12th, December, 2018

Off ice Memorandum

Subject: Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 - opportunity for revision of option to come over to revised pay structure

The undersigned is directed to invite attention to Rules 5 & 6 of the CCS (RP) Rules, 2016 regarding exercise of option to come over to the revised pay structure effective from 1.1.2016 as notified by the CCS(RP) Rules, 2016 and to say that the said option was to be exercised within 3 months of the date of notification, i.e., 25.7.2016, of the said Rules. The Rule 6(4) thereof provides that the option once exercised shall be final.

2. The Staff Side of the National Council (JCM) has requested that employees may be given another opportunity to re-exercise their option in view of certain hardships caused to certain employees. A number of references have also been received in this Ministry, proposing that the affected employees may be given an opportunity to re-exercise their option.

3. The matter has been considered and the President is pleased to decide that in relaxation of the stipulation contained in Rule 6(4) of CCS(RP) Rules, 2016, the Central Government employees, who have already exercised their option to come over to the revised pay structure as notified by the CCS(RP) Rules, 2016, shall be permitted another opportunity to revise their initial option in terms of Rules 5 & 6 thereof. The revised option shall be exercised within a period of 3 months from the date of issue of these orders. The option once exercised in terms of these orders shall be final and shall not be liable to any further change under any circumstances. All other terms and conditions as laid down in the said Rules 5 and 6 shall continue to be applicable.

4. It is obvious that in respect of those employees who have already exercised option to come over to the revised pay structure from 01.01.2016 itself or in whose case the revised pay structure took effect from 01.01.2016 and who re-exercise their option under these orders to come over to the revised pay structure from a date subsequent to 01.01.2016 as per Rule 5 of CCS (RP) Rules, 2016, the arrears on account of revised pay already drawn by them from 01.01.2016 up to the date from which they now opt to come over to the revised pay structure shall be recovered.

5. In their application to the employees serving in IA&AD, these orders were issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Amar Nath Singh)
Director

To,

1. All Ministries/Departments of the Government of India (As per standard distribution list)
2. Guard File
3. NIC with the request that the same be posted on the website of Ministry of Finance, Department of Expenditure.